

Social Media and AI: Public Communication and Information Outreach.



A workshop by the name of Reform - Perform -Transform and Inform was conducted in the Secretariat Conference Hall, Jaipur, in a meeting of senior officers of all departments. The theme of the Reform-Perform-Transform and Inform workshop was to enhance systematic and the current communication in order to ensure that government policies and schemes reach to the targeted beneficiaries and also to enhance the implementation and monitoring. Chief Secretary Shri V. Srinivas remarked the departments should embrace evolving and innovative approaches of publicity and outreach through the application of social media tools alongside conventional approaches. Secretary, Ministry of Information & Broadcasting (GoI), Shri Sanjay Jaju emphasized that simplicity of language, important details, credibility and emotional appeal of information makes the information more powerful. Another important point that was noted during the Reform-Perform-Transform and Inform workshop is that brief positive news, success stories, and achievements in the form of infographics are very effective on social media.

The Chief Secretary sent the following messages:-

- Communication is a key element to make government policies and schemes available in target groups.
- Communication should be regular and revised in a better implementation and monitoring.

- The modern outreach modes such as new social media should be utilized in the departments.
- DIPR has embraced innovations to proliferate the communication and reach of people.
- Lakh of people watched and shared such content as Army Day Parade, Employment Calendar, and Road Safety videos published by DIPR.

Secretarial contributions, Ministry of I&B (GoI).

- There should be the passing of government information in a simple lingo with critical facts and plausibility.
- Emotional appeal will enhance effectiveness and connectivity with the people.
- Examples Provided: GST campaign by direct messaging like GST Bachat Utsav.
- Such campaigns as Har Ghar Tiranga, Swachh Bharat Abhiyan, Ek Ped Maa Ke Naam demonstrate that less complex and direct appeals are more efficient.
- Brief, positive news and success stories posted in the form of infographics are successful on social media.

AI application and Misinformation addressing.

Platform-Specific Communication

- The workshop highlighted the necessity to engage the people via the social media using platform-specific strategies.

Artificial Intelligence to Public Information Integrity.

- It was mentioned that AI should be applied by the government to combat fake and misleading news shared in the social media.

Respondents and Departmental Following-Up.

- On effective communication in government and central innovations, DG, PIB, Smt. Anupama Bhatnagar delivered.
- Shri B. Narayanan, Principal DG, MMW & EMMC, gave a talk on Platform-Specific Communication.
- Additional Chief Secretaries, Principal Secretaries, Joint Secretaries and other officers brought on ideas in an interactive session.
- Secretary, DIPR, Shri Sandesh Nayak said that suggestions will be taken by DIPR and an effective strategy will be followed to make schemes reach the people.
- Shri Rakesh Sharma, commissioner, DIPR, informed participants about innovations of DIPR and social media experiments.

Conclusion

The workshop Reform-Perform-Transform and Inform indicated that specific, believable, and emotionally appealing communication is the key to effective governance. Having a more robust combination of conventional outreach, social media tools, infographics, and AI-based anti-misinformation work, the departments want to make sure the government schemes and programmes are more effectively delivered to the general population.

MCQs (RAS Prelims)

Q1: The workshop was reform–perform transformation and inform that were mainly centered on:

- A. More tax collections exploited by awareness drives.
- B. Enhancing a systematic, current communication to enhance scheme implementation and outreach.
- C. Introduction of new labour market guarantee program.
- D. Disaster management operations training officers.

Answer: B

Explanation: The workshop emphasized the importance of systematic and updated communication at the core to achieve the target groups receiving the government schemes and the enhancement of implementation and monitoring, such as using modern and social media tools.

Q2: The Secretary, Ministry of I&B (GoI) noted that information of the government will be more effective when it is conveyed with:

- A. The use of complicated terminology and intricate legal jargon.
- B. Statistical data only without narrative.
- C. Simply wording, trustworthiness, important facts, and emotion.
- D. Use of print media advertising exclusively.

Answer: C

Explanation: Shri Sanjay Jaju emphasized that the use of plain language, credibility, critical details, and emotion make communication more efficient as an example, the campaigns that used straightforward and direct messages.

Q3: Why was AI proposed in the workshop primarily?

- A. Departmental budget preparation automation.
- B. Forecasting of elections.
- C. Preventing false and misleading news on social media.
- D. Abolishing the conventional outreach approaches completely.

Answer: C

Goal: The workshop identified that AI should be employed to prevent fake and misleading news being spread on the social media, which facilitates reliable communication and outreach with people.

सामाजिक माध्यम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता: जनसंचार एवं सूचना-पहुंच

सचिवालय सम्मेलन कक्ष, जयपुर में “सुधार-प्रदर्शन-रूपांतरण और सूचना” नामक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस कार्यशाला का उद्देश्य व्यवस्थित एवं अद्यतन संचार को सशक्त बनाना था ताकि सरकारी नीतियाँ एवं योजनाएँ लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचें तथा क्रियान्वयन और निगरानी बेहतर हो। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि विभागों को पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ सामाजिक माध्यम के उपकरणों का उपयोग करते हुए प्रचार-प्रसार और जन-पहुंच के नवीन एवं आधुनिक तरीकों को अपनाना चाहिए। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू ने कहा कि सरल भाषा, आवश्यक विवरण, विश्वसनीयता और भावनात्मक अपील के साथ प्रस्तुत सूचना अधिक प्रभावी होती है। कार्यशाला में यह भी रेखांकित किया गया कि सकारात्मक समाचार, सफलता-कथाएँ और उपलब्धियाँ यदि सूचना-चित्रों के रूप में संक्षेप में प्रस्तुत की जाएँ तो वे सामाजिक माध्यम पर अधिक प्रभावी रहती हैं।

मुख्य सचिव के प्रमुख संदेश

- सरकारी नीतियों एवं योजनाओं को लक्षित समूहों तक पहुँचाने में संचार एक प्रमुख तत्व है।
- बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी के लिए संचार नियमित तथा समय-समय पर अद्यतन होना चाहिए।
- विभागों को नए सामाजिक माध्यम जैसे आधुनिक जन-पहुंच साधनों का उपयोग करना चाहिए।
- राज्य जनसंपर्क निदेशालय ने जनसंचार और जन-पहुंच बढ़ाने के लिए नवाचार अपनाए हैं।

- सेना दिवस परेड, रोजगार पंचांग, तथा सड़क सुरक्षा जैसे वीडियो/सामग्री को लाखों लोगों ने देखा और साझा किया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) के सचिव के प्रमुख बिंदु

- सरकारी सूचना सरल भाषा में, महत्वपूर्ण तथ्यों और विश्वसनीयता के साथ संप्रेषित की जानी चाहिए।
- भावनात्मक अपील से प्रभावशीलता बढ़ती है और जनता से जु़़ार मजबूत होता है।
- उदाहरण: वस्तु एवं सेवा कर अभियान में “वस्तु एवं सेवा कर बचत उत्सव” जैसे सीधे संदेश।
- “हर घर तिरंगा”, “स्वच्छ भारत अभियान” और “एक पेड़ माँ के नाम” जैसे अभियानों से स्पष्ट है कि कम जटिल और सीधे संदेश अधिक प्रभावी होते हैं।
- संक्षिप्त सकारात्मक समाचार और सफलता-कथाएँ यदि सूचना-चित्रों के रूप में प्रस्तुत हों, तो सामाजिक माध्यम पर अच्छा प्रदर्शन करती हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग एवं भ्रामक सूचना से निपटना

मंच-विशिष्ट संचार

- कार्यशाला में यह आवश्यकता बताई गई कि मंच-विशिष्ट रणनीतियों के माध्यम से सामाजिक माध्यम पर जनता तक पहुँचा जाए।

जनसूचना की विश्वसनीयता हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता

- यह उल्लेख किया गया कि सामाजिक माध्यम पर फैलने वाली झूठी और भ्रामक खबरों पर नियंत्रण के लिए सरकार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए।

वक्ता एवं विभागीय अनुवर्ती कार्यवाही

- प्रेस सूचना ब्यूरो की महानिदेशक श्रीमती अनुपमा भट्टनागर ने प्रभावी सरकारी संचार और केंद्रीय नवाचारों पर प्रस्तुति दी।
- एमएमडब्ल्यू एवं ईएमएमसी के प्रधान महानिदेशक श्री बी. नारायणन ने “मंच-विशिष्ट संचार” विषय पर प्रस्तुति दी।
- संवाद सत्र में अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, संयुक्त सचिवों एवं अन्य अधिकारियों ने सुझाव और अनुभव साझा किए।
- राज्य जनसंपर्क निदेशालय के सचिव श्री संदेश नायक ने कहा कि विभाग सुझावों को अपनाकर योजनाओं को जनता तक पहुँचाने हेतु प्रभावी रणनीति पर कार्य करेगा।
- राज्य जनसंपर्क निदेशालय के आयुक्त श्री राकेश शर्मा ने विभागीय नवाचारों और सामाजिक माध्यम प्रयोगों की जानकारी दी।

निष्कर्ष

“सुधार-प्रदर्शन-रूपांतरण और सूचना” कार्यशाला में यह रेखांकित किया गया कि स्पष्ट, विश्वसनीय और भावनात्मक रूप से प्रभावी संचार सुशासन की कुंजी है। पारंपरिक जन-पहुंच, सामाजिक

माध्यम, सूचना-चित्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित भास्कर सूचना-रोधक प्रयासों के समन्वय से विभाग सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को सामान्य जनता तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुँचाना चाहते हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न (राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा)

1. “सुधार-प्रदर्शन-रूपांतरण और सूचना” कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य किस पर केंद्रित था?

- A. जन-जागरूकता अभियानों से कर-संग्रह बढ़ाना
- B. योजनाओं के क्रियान्वयन और जन-पहुंच हेतु व्यवस्थित, अद्यतन संचार को सशक्त करना
- C. नई श्रम बाज़ार गारंटी योजना का आरंभ
- D. अधिकारियों को आपदा प्रबंधन संचालन का प्रशिक्षण देना

उत्तर: B

कार्यशाला में व्यवस्थित और अद्यतन संचार को सरकार की योजनाएँ लक्षित समूहों तक पहुँचाने तथा क्रियान्वयन और निगरानी सुधारने का मूल आधार बताया गया, जिसमें आधुनिक और सामाजिक माध्यम उपकरणों के उपयोग पर जोर दिया गया।

2. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) के सचिव के अनुसार सरकारी सूचना अधिक प्रभावी कब होती है?

- A. जटिल शब्दावली और कठिन कानूनी भाषा के प्रयोग से
- B. केवल सांख्यिकीय आँकड़ों को बिना कथा/संदर्भ के प्रस्तुत करने से
- C. सरल भाषा, विश्वसनीयता, महत्वपूर्ण तथ्य और भावनात्मक अपील के साथ
- D. केवल मुद्रित माध्यम के विज्ञापनों पर निर्भर रहने से

उत्तर: C

श्री संजय जाजू ने बताया कि सरल भाषा, विश्वसनीयता, आवश्यक विवरण और भावनात्मक अपील के साथ संप्रेषित सूचना अधिक प्रभावी बनती है; उन्होंने सीधे और स्पष्ट संदेश वाले अभियानों के उदाहरण भी दिए।

3. कार्यशाला में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रस्ताव मुख्य रूप से किस उद्देश्य से रखा गया?

- A. विभागीय बजट निर्माण का स्वचालन
- B. चुनाव पूर्वानुमान
- C. सामाजिक माध्यम पर झूठी और भ्रामक खबरों पर रोक
- D. पारंपरिक जन-पहुंच तरीकों को पूरी तरह समाप्त करना

उत्तर: C

कार्यशाला में बताया गया कि सामाजिक माध्यम पर फैलने वाली झूठी और भ्रामक खबरों पर नियंत्रण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि जनसंचार और जन-पहुंच अधिक विश्वसनीय बन सके।

Heritage Stepwells, Shekhawati Havelis and Tourism Infrastructure: Conservation, Clearances and Air Connections.

Heritage Stepwells, Shekhawati Havelis and Tourism Infrastructure: Conservation, Clearances and Air Connections



The pending issues of Tourism and Art and Culture Department were reviewed in Jaipur in the chairmanship of the Deputy Chief Minister and Minister of Tourism and Art and Culture, Diya Kumari, in the company of the Tourism Commissioner Rukmani Riyad. The meeting was aimed at speeding up various projects in progress by implementing them within a time limit. The Deputy CM stressed that conservation of heritage stepwell (baori) was a priority of the state and instructed that an action plan and documentation should be prepared. She also checked on the developments on the conservation of Shekhawati haveli and directed that Mandawa be done as a prototype of conservation of heritage. Issues that were raised in regard to tourism infrastructure such as accommodating the hotel sector and necessity to increase air transport to enhance tourist arrival numbers were also tackled.

Significant Projects Reviewed and Time and Direction.

The Deputy CM met progress and instructed accelerated implementation according to schedules of:

- Phone app initiative
- Amer Master Plan
- Electronicization of archives.
- Media buying
- Pratap Tourist Circuit
- Pushkar Corridor
- JKK tender
- Ravindra Rangmanch re-modeling.
- RTICE Board-related matters
- A MICE Centre Land allotment.
- Albert Hall tende

Historical Preservation Concentration.

Shekhawati Havelis

- The development of conservation of Shekhawati havelis was discussed.
- Specific action plan was to be followed in order to come up with Mandawa as a heritage conservation model.

Heritage Stepwells (Baoris)

- Guidance was given to create an elaborate action plan on conservation of stepwells.
- Departments were guided by the Deputy CM to adopt other good conservation work best practices.
- She mentioned that some works on conservation work were already done on some of the stepwells.
- There is a comprehensive report on conservation work under preparation, to inform the further step of the identification and conservation of additional stepwells throughout the state.

Issues In Tourism Facilitating and Hotel Industry.

The representatives of the hotel industry were discussed in the presence of the officials of the UDH and LSG departments regarding the provision of facilities and solving problems at the hotels. Key directions included:

- The hotel industry has easier land allotment procedures and the procedures to establish new units of hotels.

- On time licenses, Fire NOC and other approvals.
- Single-window clearance as a priority in facilitating easiness of approvals and assist in tourism development contributions by the hotel industry.

Connectivity and Tourist facility Development.

- The Deputy CM indicated that the state is in the process of coming up with tourism facilities to the visitors in whatever way.
- She noted that there should be higher air connectivity by indicating that greater air connectivity has the capacity to enhance domestic and international tourist arrivals.
- Another area that the state is working on is road connectivity, train connectivity, facilities in tourist sites and the widening of infrastructure.
- During peak season of tourists, efforts will be made to ensure that the tourists do not experience inconvenience.
- The state is deliberating on ways of creating more accommodation options, such as adding room stock and increasing the number of three-stars and four-stars hotels.

Next Budget Inputs and Budget Implementation.

- According to the Deputy CM, the current financial year budget announcements have been done in a better manner.
- Critical areas that can be incorporated in the next budget were also discussed.

Conclusion

The strategy by Rajasthan is to focus on heritage conservation and also provide tourism and connectivity. The state seeks to enhance the tourist experience and boost the inflow of tourists by ensuring that stepwells are well-documented and action plans put in place, Mandawa is developed as a model of conserving haveli, facilitation of clearance of hotels through single-window mechanism and enhancing air connectivity as well as road and rail support.

MCQs (English)

Q1: The meeting under the chairmanship of Deputy CM Diya Kumari mostly examined what were the outstanding issues of the department?

- A. Department of Agriculture and Cooperation.
- B. Tourism and Art and Culture Department.
- C. Home and Disaster Management Department.

D. Energy and Mines Department.

Answer: B

Explanation : The meeting of the review of Tourism Bhawan revolved around the outstanding issues of the Tourism and Art & Culture Department and gave timely instructions on various tourism and heritage related projects.

Q2: What was the particular heritage project channeled towards Shekhawati?

A. Steel of declaring Shekhawati as a coastal tourism zone.

B. Making Mandawa a prototype of heritage conservation of Shekhawati havelis.

C. relocation of Shekhawati havelis to another museum compound.

D. Introduction of a new industrial corridor in Mandawa.

Answer: B

Explanation : The Deputy CM checked the progress of conservation of Shekhawati haveli and asked Mandawa to be designed as a model on conservation of heritage using action plan.

Q3: What was the measure that was discussed specifically in the context of curbing tourist inconvenience during peak season?

A. Lowering the entrance fees in all monuments.

B. Closure of tourist sites to do maintenance work during the high season.

C. Add more inventory of accommodation and three- and four-star hotels.

D. Limiting the entry of tourists by use of permits.

Answer: C

Explanation : The Deputy CM was concerned with the necessity to provide proper hospitality units in the period of peak season and addressed the problem of increasing the room stocks and the quantity of three-four star hotels.

विरासत बावड़ियाँ, शेखावाटी हवेलियाँ और पर्यटन अवसंरचना: संरक्षण, स्वीकृतियाँ और वायु संपर्क

जयपुर में पर्यटन एवं कला एवं संस्कृति विभाग के लंबित प्रकरणों की समीक्षा उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन एवं कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में, पर्यटन आयुक्त रुक्मणि रियाइ की

उपस्थिति में की गई। बैठक का उद्देश्य समय-सीमा के भीतर क्रियान्वयन सुनिश्चित कर विभिन्न चल रहे प्रोजेक्ट्स को तेज़ गति से आगे बढ़ाना था। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विरासत बावड़ियों का संरक्षण राज्य की प्राथमिकता है और इसके लिए कार्य योजना तथा दस्तावेजीकरण तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने शेखावाटी हवेलियों के संरक्षण की प्रगति की समीक्षा की और मंडावा को विरासत संरक्षण के मॉडल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। बैठक में पर्यटन अवसंरचना से जुड़े विषयों, होटल उद्योग को सुविधाएँ देने तथा वायु संपर्क बढ़ाकर पर्यटक आगमन को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई।

प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और समयबद्ध निर्देश

उपमुख्यमंत्री ने निम्न परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी लेकर समय-सीमा के अनुसार त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश दिए:

- फोन ऐप पहल
- आमेर मास्टर प्लान
- पुरालेखों का डिजिटलीकरण
- मीडिया बाइंग
- प्रताप पर्यटक परिपथ
- पुष्कर गलियारा
- जेकेके निविदा
- रवीन्द्र रंगमंच का नवीनीकरण
- आरटीआईसीई बोर्ड से जुड़े विषय
- माइस केंद्र हेतु भूमि आवंटन
- अल्बर्ट हॉल निविदा

विरासत संरक्षण पर विशेष ध्यान

शेखावाटी हवेलियाँ

- शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण की प्रगति पर चर्चा की गई।
- मंडावा को विरासत संरक्षण का मॉडल बनाने हेतु विशिष्ट कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।

विरासत बावड़ियाँ

- बावड़ियों के संरक्षण के लिए समग्र कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए।
- अन्य अच्छे संरक्षण कार्यों की श्रेष्ठ प्रक्रियाओं का अनुसरण करने के निर्देश दिए गए।

- उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ बावड़ियों पर संरक्षण कार्य पहले से चल रहे हैं और कुछ कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं।
- संरक्षण कार्यों का समग्र दस्तावेजीकरण तैयार किया जा रहा है, ताकि आगे किन-किन बावड़ियों का संरक्षण किया जा सकता है, इसके लिए कार्य योजना बनाकर काम किया जा सके।

पर्यटन सुविधा-प्रदान और होटल उद्योग से जुड़े मुद्दे

यूडीएच एवं एलएसजी विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में होटल उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ सुविधाएँ देने और समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। प्रमुख निर्देश:

- होटल उद्योग को भूमि आवंटन तथा नई होटल इकाइयाँ स्थापित करने की प्रक्रियाएँ सरल हों।
- लाइसेंस, अग्निशमन अनापति प्रमाणपत्र और अन्य स्वीकृतियाँ समय पर व आसानी से मिलें।
- अनुमतियों में सरलता और पर्यटन विकास में होटल उद्योग के योगदान को बढ़ाने हेतु एकल खिड़की स्वीकृति को प्राथमिकता दी जाए।

संपर्कता और पर्यटक सुविधाओं का विकास

- उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य पर्यटकों के लिए सभी प्रकार की पर्यटन सुविधाओं के विकास पर केंद्रित होकर कार्य कर रहा है।
- उन्होंने वायु संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता बताई और कहा कि इससे देशी-विदेशी पर्यटकों के आगमन में सुविधा होगी तथा पर्यटक आगमन बढ़ सकता है।
- राज्य का ध्यान सङ्केतन संपर्क, रेल संपर्क, पर्यटक स्थलों पर बेहतर सुविधाएँ तथा व्यापक अवसंरचनात्मक विकास पर भी केंद्रित है।
- पर्यटन के चरम मौसम में पर्यटकों को असुविधा न हो, इसके लिए व्यवस्थाएँ सुदृढ़ की जाएँगी।
- आवास सुविधाएँ बढ़ाने के लिए कमरों की संख्या बढ़ाने और तीन-स्टार तथा चार-स्टार होटलों की संख्या बढ़ाने के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

बजट क्रियान्वयन और आगामी बजट के लिए विचार

- उपमुख्यमंत्री के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष की बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से किया गया है।
- आगामी बजट में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हुई।

निष्कर्ष

राजस्थान की रणनीति विरासत संरक्षण के साथ पर्यटन सुविधा-प्रदान और संपर्कता को सशक्त करने की है। राज्य बावड़ियों के दस्तावेजीकरण और कार्य योजना, मंडावा को हवेली संरक्षण के मॉडल

के रूप में विकसित करने, एकल खिड़की स्वीकृति के माध्यम से होटल स्वीकृतियों को सरल बनाने तथा वायु संपर्क, सड़क और रेल समर्थन को बेहतर करके पर्यटक अनुभव सुधारने और पर्यटक आगमन बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

बहुविकल्पीय प्रश्न (राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा)

1. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य रूप से किस विभाग के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई?

- A. कृषि एवं सहकारिता विभाग
- B. पर्यटन एवं कला एवं संस्कृति विभाग
- C. गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग
- D. ऊर्जा एवं खनिज विभाग

उत्तर: पर्यटन एवं कला एवं संस्कृति विभाग

यह समीक्षा बैठक पर्यटन भवन में पर्यटन एवं कला एवं संस्कृति विभाग के लंबित प्रकरणों पर केंद्रित थी, जिसमें पर्यटन और विरासत से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स को समय-सीमा के अनुसार तेज़ी से पूरा करने के निर्देश दिए गए।

2. शेखावाटी से संबंधित कौन-सा विशिष्ट विरासत संरक्षण निर्देश दिया गया?

- A. शेखावाटी को तटीय पर्यटन क्षेत्र घोषित करना
- B. मंडावा को शेखावाटी हवेली संरक्षण के मॉडल के रूप में विकसित करना
- C. शेखावाटी की हवेलियों को एक नए संग्रहालय परिसर में स्थानांतरित करना
- D. मंडावा में नया औद्योगिक गलियारा शुरू करना

उत्तर: मंडावा को शेखावाटी हवेली संरक्षण के मॉडल के रूप में विकसित करना

बैठक में शेखावाटी हवेलियों के संरक्षण की प्रगति की समीक्षा की गई और मंडावा को विरासत संरक्षण का मॉडल बनाने हेतु कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।

3. पर्यटन के चरम मौसम में पर्यटकों की असुविधा कम करने के लिए कौन-सा उपाय चर्चा में रहा?

- A. सभी स्मारकों की प्रवेश फीस घटाना
- B. चरम मौसम में पर्यटक स्थलों को रखरखाव हेतु बंद करना
- C. आवास इकाइयों की क्षमता बढ़ाना और तीन-स्टार व चार-स्टार होटलों की संख्या बढ़ाना
- D. परमिट प्रणाली से पर्यटकों के प्रवेश को सीमित करना

उत्तर: आवास इकाइयों की क्षमता बढ़ाना और तीन-स्टार व चार-स्टार होटलों की संख्या बढ़ाना

चरम पर्यटन मौसम में पर्याप्त ठहराव सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए कमरे बढ़ाने, इन्वेंट्री बढ़ाने और तीन-स्टार व चार-स्टार होटलों की संख्या बढ़ाने पर विचार की बात कही गई।

January 23, 2026

Rajasthan Tableau on Republic Day parade; Usta Art in Bikaner; Bharat Parv.



The Rajasthan tableau will reappear this year on the Delhi Kartavya Path with Republic Day parade since it was not provided a spot last year. The Rajasthan tableau will be on this occasion a great display of the legendary golden Usta art of Bikaner. Usta art is gold work, carved upon camel leather and is considered a royal craft and exquisite ornamentation. The tableau will also represent folk performers, such as a Ravanahatha musician, and such cultural items as Gair folk dance. In addition to the parade, Bharat Parv at Red fort is also a significant large scale exhibition of tableaux between January 26 and January 31.

The Rajasthan Tableau has some important characteristics.

- The front portion depicts a sculpture of a folk artist playing the Ravanahatha.
- The sculpture as an artist is meant to rotate (180-degree movement is indicated).
- Framed motifs, like a surahi (vessel) and lamps are pointed out by side panels, bearing Usta art motifs.
- The back part has a huge sculpture of camel with a rider and is ornamented.
- The craftspeople are depicted as old-fashioned workers, the sample of leather craft is presented in Usta-art style arches.
- The front and the two sides of the tableau are illustrated with gair folk dance performers.

About Usta Art of Bikaner

- Usta art is a particular royal craft of Bikaner, which is characterised by golden decoration.
- It is correlative with gold meenakari-style ornament and detailing.
- It is associated with the Persian roots and evolved in Mughal courts and transferred to Bikaner under the patronage of Raja Rai Singh through the hands of master artists.
- This is done by carving the camel leather using a special technique.
- It applies raised golden work in 24-carat gold leaf and with natural colours (Munawwati).
- Originally applied to such objects as a kupi (water container), lampshades, and decorative boxes.
- It has also over the time been applied on materials like wood, marble, glass and walls.
- Geographical Indication has been granted to the craft.

The Situation and Statistics of Bharat Parv.

- Bharat Parv is an annual event that is conducted between January 26 and January 31, at the Red Fort.
- There are 31 tableaux (states and central ministries) participating in the Republic Day parade.
- Bharat parv exhibits 43 tableaux.
- Rajasthan had not been given space in Kartavya Path last year, therefore its tableau was exhibited at Bharat Parv.
- This year, the tableau will be on Kartavya Path and special attention will be given to the Usta art of Bikaner.

Conclusion

The reintroduction of the Rajasthan tableau to Kartavya Path points to a new national stage of cultural identity of the state. Through the showcasing of the GI-tagged Usta art of Bikaner, folk music and dance culture, the tableau enhances the cultural awareness and sells the heritage crafts of Rajasthan in a well-attended national show. Bharat Parv also opens up even more to the people by using more tableaux showcasing at the Red Fort on the period January 26 to January 31.

MCQs (English)

Q1: The important change that was made in the news about the Rajasthan tableau was that it:

- A. It will not be shown in the parade, just at Bharat Parv.
- B. Tries to come to Kartavya Path a year later.
- C. Has replaced central ministry tableau.
- D. Only in Bikaner a local exhibition.

Answer: B

Explanation The report informs that the tableau of Rajasthan will be again observed on Kartavya Path this year, but last year it was not included in the Republic Day parade, and was instead held at Bharat Parv.

Q2: What do you consider to be the best description of Usta art as cited in the news by Bikaner?

- A. Stone carving with only the chemical dyes.
- B. Gold on camel leather 24-carat gold leaf, natural colours.
- C. Embroidery on cotton material and using metallic thread only.
- D. Bronze casting mainly used to make temple bells.

Answer: B

Explanation: The news discusses that the Usta art is the process that involves the work on camel leather and making raised golden work with 24-carat gold leaf and natural colours, which are also known to be used in royal ornamentation.

Q3: According to the news, Bharat Parv is conducted:

- A. January 15 to January 20 in Kartavya Path.
- B. January 26 -31 at the Red Fort.
- C. India gate, January 1 to January 7.
- D. February 1 to February 5, at Rajasthan House.

Answer: B

Explanation : According to the report, Bharat Parv is an annual event of 31 days between January 26 to January 31 at the Red Fort where tableaux is on display to the citizens.

गणतंत्र दिवस पर राजस्थान की झांकी; बीकानेर की उस्ता कला; भारत पर्व

राजस्थान की झांकी इस वर्ष दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में फिर से दिखाई देगी, क्योंकि पिछले वर्ष इसे स्थान नहीं मिला था। इस बार झांकी में बीकानेर की प्रसिद्ध स्वर्ण उस्ता कला को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। उस्ता कला ऊँट की खाल पर की जाने वाली स्वर्णकारी नक्काशी/अलंकरण शैली है, जिसे राजसी शिल्प और सूक्ष्म सजावटी काम के लिए जाना जाता है। झांकी में रावणहाथा वादक जैसे लोक कलाकार तथा गैर लोकनृत्य जैसे सांस्कृतिक पक्ष भी दिखाए जाएंगे। परेड के साथ ही लाल किले में 26 जनवरी से 31 जनवरी तक भारत पर्व के दौरान भी झांकियों का बड़ा प्रदर्शन होता है।

राजस्थान झांकी की प्रमुख विशेषताएँ

- अग्र भाग में रावणहाथा बजाते हुए एक लोक कलाकार की प्रतिमा दिखाई गई है।
- कलाकार की प्रतिमा के 180 डिग्री घूमने का संकेत दिया गया है।
- पार्श्व पैनलों पर उस्ता कला के रूपांकन वाले फ्रेम में सुराही (पात्र) और दीपक जैसे चित्रांकन दिखाए गए हैं।
- पिछला भाग एक बड़े ऊँट और उस पर सवार सवारी की प्रतिमा के साथ सजाया गया है।
- कारीगरों को परंपरागत शैली में कार्य करते हुए दिखाया गया है और उस्ता कला शैली की मेहराबों में चमड़ा शिल्प के नमूने प्रदर्शित हैं।
- झांकी के अग्र भाग तथा दोनों ओर गैर लोकनृत्य के कलाकारों का चित्रण किया गया है।

बीकानेर की उस्ता कला

- उस्ता कला बीकानेर की एक विशिष्ट राजसी शिल्पकला है, जिसकी पहचान स्वर्ण अलंकरण से होती है।
- इसे स्वर्ण मीनाकारी शैली की सजावट और सूक्ष्म कारीगरी से जोड़ा गया है।
- इसका संबंध फ़ारसी मूल से बताया गया है, जो मुगल दरबारों में विकसित होकर राजा राय सिंह के संरक्षण में कुशल कारीगरों के माध्यम से बीकानेर पहुँची।
- यह कार्य ऊँट की खाल को विशेष तकनीक से तराशकर/नक्काशी करके किया जाता है।
- इसमें 24 कैरेट स्वर्ण पत्तर और प्राकृतिक रंगों से उभरा हुआ स्वर्णकारी काम किया जाता है, जिसे मुनाव्वती कहा गया है।
- प्रारंभ में इसका उपयोग कूपी (पानी का पात्र), लैम्पशेड और सजावटी डिब्बों जैसी वस्तुओं पर किया जाता था।
- समय के साथ इसका उपयोग लकड़ी, संगमरमर, काँच और दीवारों जैसी सतहों पर भी होने लगा।
- इस शिल्प को भौगोलिक संकेतक प्राप्त है।

भारत पर्व की स्थिति और आँकड़े

- भारत पर्व हर वर्ष 26 जनवरी से 31 जनवरी तक लाल किले में आयोजित होता है।
- गणतंत्र दिवस परेड में कुल 31 झांकियाँ (राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों की) भाग लेती हैं।
- भारत पर्व में कुल 43 झांकियाँ प्रदर्शित होती हैं।
- पिछले वर्ष राजस्थान को कर्तव्य पथ पर स्थान नहीं मिला था, इसलिए उसकी झांकी भारत पर्व में प्रदर्शित की गई थी।
- इस वर्ष झांकी को कर्तव्य पथ पर स्थान मिला है और इसमें बीकानेर की उस्ता कला पर विशेष ध्यान रखा गया है।

निष्कर्ष

कर्तव्य पथ पर राजस्थान की झांकी की वापसी राज्य की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर फिर से प्रमुख मंच देती है। बीकानेर की भौगोलिक संकेतक-प्राप्त उस्ता कला, लोक वादन और लोकनृत्य के माध्यम से यह प्रस्तुति राजस्थान की विरासत शिल्प परंपराओं के प्रति जागरूकता बढ़ाती है। वहीं, भारत पर्व में 26 से 31 जनवरी के बीच झांकियों का व्यापक प्रदर्शन जनता की पहुँच को और विस्तारित करता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न (हिन्दी)

Q1: राजस्थान की झांकी से संबंधित समाचार में मुख्य परिवर्तन क्या बताया गया है?

- A. झांकी केवल भारत पर्व में दिखाई जाएगी, परेड में नहीं
B. झांकी पिछले वर्ष स्थान न मिलने के बाद इस वर्ष कर्तव्य पथ पर फिर दिखाई देगी
C. राजस्थान की झांकी को केंद्रीय मंत्रालय की झांकी से बदल दिया गया है
D. झांकी केवल बीकानेर में स्थानीय प्रदर्शनी के रूप में दिखाई जाएगी

उत्तर: B

समाचार के अनुसार राजस्थान की झांकी इस वर्ष कर्तव्य पथ पर फिर दिखाई देगी, जबकि पिछले वर्ष इसे परेड में स्थान नहीं मिला था और इसे भारत पर्व में प्रदर्शित किया गया था।

2. समाचार के अनुसार बीकानेर की उस्ता कला का सही वर्णन क्या है?

- A. केवल रासायनिक रंगों से पत्थर पर की गई नक्काशी
B. ऊंट की खाल पर 24 कैरेट स्वर्ण पत्तर और प्राकृतिक रंगों से उभरा हुआ स्वर्णकारी काम
C. केवल सूती कपड़े पर धातु धागों से कढ़ाई
D. मुख्यतः मंदिर की घंटियों के लिए कांस्य ढलाई

उत्तर: B

समाचार में बताया गया है कि उस्ता कला ऊंट की खाल पर विशेष तकनीक से काम करके 24 कैरेट स्वर्ण पत्तर और प्राकृतिक रंगों के साथ उभरा हुआ स्वर्णकारी अलंकरण करती है, जिसे राजसी शिल्प के रूप में जाना जाता है।

3. समाचार के अनुसार भारत पर्व कब और कहाँ आयोजित होता है?

- A. 15 जनवरी से 20 जनवरी तक, कर्तव्य पथ पर

- B. 26 जनवरी से 31 जनवरी तक, लाल किले में
- C. 1 जनवरी से 7 जनवरी तक, इंडिया गेट पर
- D. 1 फरवरी से 5 फरवरी तक, राजस्थान भवन में

उत्तर: B

समाचार के अनुसार भारत पर्व हर वर्ष 26 जनवरी से 31 जनवरी तक लाल किले में आयोजित होता है, जहाँ जनता के लिए झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है।

RASonly

Gram Utthan Camps; Last-Mile Welfare Scheme Implementation Plan in Udaipur.



The program was kicked off with a very successful review meeting with the head of the Education department. Rajasthan was the first state to officially start Gram Utthan Camps that were to be hosted at Girdawar Circle level within the state. It was introduced at the state-level in Sirohi by the presence of Chief Minister Bhajanlal Sharma. In Udaipur, a district level-launch was held at the Pandit Deendayal Upadhyay Auditorium (Municipal Corporation premises) where TAD Minister Babulal Kharadi was the chief guest. In the Udaipur event, the state programme was displayed on live telecast on an LED screen.

These camps will be arranged in 89 ILR circles in the Udaipur district. The aim of the stated is to give the advantages of the different departments public welfare plans to the citizens under a single location under these camps.

Key Administrative Plan

- Gram Utthan Camps will be at the level of statewide Girdawar Circle.
- District of Udaipur: 89 ILR circles will be used to set up camps.
- The camps are designed to provide various departments welfare scheme benefits in one window type set up at a single location.
- The district event had live telecast of the state launch in an LED screen.

Words Spoken in the course of the Programme (TAD Minister Babulal Kharadi)

- He said that despite 78 years of Independence, farmers have been lacking even fundamental amenities.
- He said that India is developing at a very high pace with the leadership of Prime Minister, Narendra Modi.
- He said that previous corruption in the MGNREGA had been checked and that the Prime Minister had introduced the VBG Ram Ji Act that would give direct benefits to the poor citizens.
- He said that the government was striving to expand Kisan Samman Nidhi to 12000 rupees.
- He explained that different recruitment examination has been done fairly and without any dispute.
- He called on people to make the best out of the Gram Utthan Camps.

The Importance of This to RAS Exam (Governance Focus).

- Shows a governance model which consists of the last-mile services delivery and single-location access to multiple schemes.
- Underlines that camp-based administration is used to reach out to more quickly and facilitate grievances/schemes at the local level.
- Presents district implementation planning by specific administrative units such as ILR circles.

Conclusion

The statewide launch of Gram Utthan Camps strengthens last-mile delivery by providing multi-department welfare benefits at a single location through Girdawar Circle-level camps. With 89 ILR circles in Udaipur, it enables faster outreach, easier access, and improved field-level monitoring.

MCQs (English)

Q1: At what level will the Gram Utthan Camps that were established in Rajasthan be organized?

- A. Village Panchayat level
- B. Girdawar Circle level
- C. District Headquarters level.
- D. State Secretariat level

Answer: B

Explanation: According to the programme announcement, Gram Utthan Camps will be held at Girdawar Circle level throughout the state to allow the enjoyment of the multiple departments welfare schemes at a single place.

Q2: As per the programme information, what number of ILR circles in Udaipur district will contain Gram Utthan Camps?

- A. 49
- B. 78
- C. 89
- D. 109

Answer: C

Elaboration: Gram Utthan Camps will be held in 89 ILR circles in the district of Udaipur, and the explanation is that citizens might receive the benefits of the welfare scheme under one roof.

Q3: What was included in the district-level launch arrangement in Udaipur?

- A. The state-level programme was only done on radio.
- B. The programme at the state-level was demonstrated on the live telecast on an LED screen.
- C. The launch was done online completely without a physical location.
- D. The show occurred within the Rajasthan assembly.

Answer: B

Details: The region event in Udaipur district featured a live telecasting of the state-level launch programme that was shown on an LED screen at the venue.

ग्राम उत्थान शिविर; उदयपुर में अंतिम छोर तक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की कार्ययोजना

राजस्थान ने गिरदावर सर्किल स्तर पर आयोजित होने वाले ग्राम उत्थान शिविरों का औपचारिक शुभारंभ किया। राज्य स्तर पर शुभारंभ सिरोही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में हुआ। उदयपुर में जिला स्तर का शुभारंभ नगर निगम परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित किया गया, जहाँ जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के मंत्री बाबूलाल खराड़ी मुख्य अतिथि रहे। उदयपुर कार्यक्रम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एलईडी स्क्रीन पर दिखाया गया।

उदयपुर जिले में ये शिविर 89 आईएलआर सर्किलों पर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का उद्देश्य विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है।

प्रमुख प्रशासनिक कार्ययोजना

- ग्राम उत्थान शिविर राज्यभर में गिरदावर सर्किल स्तर पर आयोजित होंगे।
- उदयपुर जिला: 89 आईएलआर सर्किलों पर शिविर लगाए जाएंगे।
- शिविरों में विभिन्न विभागों की योजनाओं के लाभ एक ही स्थान पर एकीकृत व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे।
- जिला स्तर के कार्यक्रम में राज्य स्तरीय शुभारंभ का सीधा प्रसारण एलईडी स्क्रीन पर किया गया।

कार्यक्रम में दिए गए वक्तव्य (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी)

- उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के 78 वर्ष बाद भी किसान मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है।
- उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेज गति से प्रगति कर रहा है।
- उन्होंने कहा कि मनरेगा में पहले के अष्टाचार पर रोक लगी और प्रधानमंत्री ने वीबीजी रामजी अधिनियम लागू किया, जिससे गरीब जनता को सीधा लाभ मिलेगा।
- उन्होंने कहा कि सरकार किसान सम्मान निधि को 12,000 रुपये तक बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।
- उन्होंने कहा कि विभिन्न भर्ती परीक्षाएँ निष्पक्ष और निर्विवाद रूप से आयोजित की गई हैं।
- उन्होंने आमजन से ग्राम उत्थान शिविरों का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए महत्व (शासन-केंद्रित)

- अंतिम छोर तक सेवा-प्रदान और एक स्थान पर अनेक योजनाओं की पहुँच वाला शासन मॉडल सामने आता है।
- शिविर आधारित प्रशासन के माध्यम से त्वरित जन-पहुँच और योजना-सुविधा/समस्या-समाधान की व्यवस्था पर जोर दिखता है।
- आईएलआर सर्किल जैसी प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर जिला-स्तरीय क्रियान्वयन योजना स्पष्ट होती है।

निष्कर्ष

ग्राम उत्थान शिविरों का राज्यव्यापी शुभारंभ अंतिम छोर तक सेवा-प्रदान को सशक्त करता है। गिरदावर सर्किल स्तर पर एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ उपलब्ध होगा। उदयपुर के 89 आईएलआर सर्किलों से पहुँच तेज होगी, प्रक्रिया सरल होगी और मैदानी स्तर की

निगरानी बेहतर होगी।

बहुविकल्पीय प्रश्न (हिन्दी)

1. राजस्थान में ग्राम उत्थान शिविर मुख्यतः किस स्तर पर आयोजित किए जाएंगे?

- A. ग्राम पंचायत स्तर
- B. गिरदावर सर्किल स्तर
- C. जिला मुख्यालय स्तर
- D. राज्य सचिवालय स्तर

उत्तर: B

घोषणा के अनुसार ग्राम उत्थान शिविर राज्यभर में गिरदावर सर्किल स्तर पर आयोजित होंगे, ताकि विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा सके।

2. कार्यक्रम के अनुसार उदयपुर जिले में कितने आईएलआर सर्किलों पर ग्राम उत्थान शिविर लगाए जाएंगे?

- A. 49
- B. 78
- C. 89
- D. 109

उत्तर: C

उदयपुर जिले में 89 आईएलआर सर्किलों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि नागरिकों को विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिल सके।

3. उदयपुर में जिला स्तरीय शुभारंभ व्यवस्था में कौन-सी बात शामिल थी?

- A. राज्य स्तरीय कार्यक्रम का प्रसारण केवल रेडियो पर हुआ
- B. राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एलईडी स्क्रीन पर दिखाया गया
- C. शुभारंभ पूरी तरह केवल ऑनलाइन हुआ, कोई स्थल नहीं था
- D. कार्यक्रम विधानसभा भवन के भीतर आयोजित हुआ

उत्तर: B

उदयपुर के कार्यक्रम में राज्य स्तरीय शुभारंभ का सीधा प्रसारण एलईडी स्क्रीन के माध्यम से दिखाया गया।



January 23, 2026

RASonly